प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

एल.पी.जी.–आपूर्ति

तेल विपणन कम्पनियों के राज्यस्तरीय समन्वयक आई.एल. नेगी ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में पैट्रोलियम उत्पादों व एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से समान्य और पर्याप्त है। शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि विपणन कम्पनियां वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सक्षम है और राज्य में मोटर स्पिरिट एम.एस. व हाई–स्पीड डीज़ल एच.एस.डी की स्टॉक स्थिति सामान्य बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव ईंधनों की उपलब्धता के लिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। एल.पी.जी. के संदर्भ में नेगी ने बताया कि बॉटलिंग प्लांटस पर स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है और स्टॉक निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कम्पनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने सहित वितरण में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आई. एल. नेगी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे घबराहट में अनावश्यक खरीददारी न करें और गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल डिज़िटल माध्यम से करे।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है क्योंकि प्रदेश के संसाधनों पर उनका भी सम्मान अधिकार है। वे कल शिमला से वर्चुअल माध्यम से चम्बा जिला के 35 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट संवाद के दौरान बोल रहे थे। वर्तमान में यह बच्चे दमन और दीप के शैक्षणिक भ्रमण पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार उनकी शिक्षा और कोचिंग का खर्च बहन कर रही है इसके अलावा विवाह के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के तहत भ्रमण करने वाले यह बच्चे जिला के साहो, पांगी, चम्बा और चिल्ली तीसा के बाल देखभाल संस्थानों से है। 31 मार्च से शुरू हुआ यह शैक्षणिक भ्रमण 7 अप्रैल तक चलेगा।

गेंहू खरीद

सिरमौर जिला में 8 अप्रैल से शुरू होने वाली गेंहू की खरीद के लिए खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला खाद्य व नागरिक आपूर्ति नियंत्रक शमशेर सिंह ने बताया कि गेंहू की खरीद के लिए विभाग द्वारा पांवटा साहिब और धौलाकुआं को खरीद केंद्र बनाया गया है जहां किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार 5 सौ 85 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जोकि गत वर्ष के मुकाबले एक सौ 60 रुपये अधिक है। शमशेर सिंह ने कहा कि गेंहू बेचने के लिए किसानों को पहले ऑनलाईन पॉर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जो एक मार्च से शुरू हो चुका है।

जैसा की आपको विधित ही है कि गत वर्ष की भांति जिला सिरमौर में पांवटा साहिब ओर धौलाकुआं की मंडियों में गेंहू की खरीद होनी है। जो भारत सरकार इसका समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया गया है जो पिछले साल की तुलना में करीब 160 रुपये अधिक निर्धारित किया गया है कुल मिलाकर जिला सिरमौर के लिए 10 हजार क्विंटल गेंहू की खरीद का टारगेट निर्धारित किया गया है

ऑनलाईं पोर्टल के माध्यम से ही होना है मॉसचर की समस्या के समाधान के लिए एग्रिकल्चर का स्टाफ मौजूद रहता है।

कार्यशाला

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आज से दो दिवसीय एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें देश–विदेश के डेढ़ सौ से अधिक भूवैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने बताया कि ये कार्यशाला 1905 के कांगड़ा भूकंप की स्मृति में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, नीतिनिर्माता और विशेषज्ञ हिमालयी टैक्टोनिकस भूकंप की बढ़ती घटनाओं सहित जलवायू परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन का उदेश्य देश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच मुक्त बनाना है। मिशन के तहत अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। जिसमें पांच लाख 87 हजार से अधिक गावों को खुले में शौच मुक्त का दर्जा और स्वच्छता व्यवहार में बड़ा बदलाव लाकर स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बेहतर स्वच्छता के चलते भारत में डायरिया से होने वाली मौतों में तीन लाख की कमी आई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का उदेश्य गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने सहित ठोस व तरल कचरे का उचित प्रबंधन करना है। ऊना जिला के पांचों विकास खण्डों में इस मिशन के तहत गत वित्त वर्ष के दौरान बेहतर कार्य किया गया है विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता–– डिस्पैच–– ''40''

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गत वित्त वर्ष के दौरान ऊना ज़िला के पांचों विकास खंडों में स्वच्छता के अनेक मदों में कार्यों को अमलीजामा पहनाया गया । ऊना विकास खंड में 48 लाख रुपये खर्च कर 13 ग्राम पंचायतों में ग्रे पानी प्रबंधन कार्यों को पूरा किया गया, जबकि ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों में साढ़े 14 लाख रुपये व्यय किए गए। ज़िला के प्रत्येक विकास खण्ड में 240 निजी शौचालय निर्मित किए गए हैं जिनपर कुल 1 करोड़ 44 लाख रुपये व्यय किए गए हैं । इसके अलावा, सभी विकास खंडों में 3 करोड़ 24 लाख रुपये व्यय कर लगभग डेढ़ सौ सामुदायिक स्वच्छता परिसर कार्यों को पूरा किया गया । मिशन में चलाये गए जन–जागरूकता अभियानों से प्रेरित होकर स्थानिय लोग इन संरचनाओं द्वारा स्वच्छता के सपनों को साकार कर रहे हैं । आकाशवाणी समाचारों के लिए ऊना से मैं राजेश शर्मा।

समस्या

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य व परिवहन जैसी मुलभूत सुविधाओं की अनदेखी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्रिलोकनाथ पंचायत के प्रधान दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंसा गांव के स्वास्थ्य केंद्र में पिछले एक साल से डॉक्टर का पद रिक्त चल रहा है, जिसके चलते त्रिलोकनाथ सहित शकोली और किशोरी पंचायत के करीब पांच हजार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए दूरदराज क्षेत्रों का रूख करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उदयपुर–त्रिलोकनाथ–केलंग रूट बस सेवा ठप्प होने से रोजाना मरीजों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान सहित स्थानीय जनता ने इन समस्याओं के तुरंत समाधान की सरकार व प्रशासन से मांग की है।